

एक नजर नगदी समेत 3 टग पकड़े गये



—भारतीय बस्ती संवाददाता— बस्ती। कलकत्ती पुलिस, स्वाट और सविलास टीम ने सासे दाम पर सोना बेचने का लालच देकर ठगी करने वाले एक अरजजनपदीय गिरोह का भंडाखंड किया है। पुलिस ने गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से तीन लाख रुपये नकद और करीब 3.09 किलोग्राम नकली सोना बरामद किया गया है।

अपर पुलिस अधीक्षक श्याम कांत ने बताया कि थाना कलकत्ती और थाना पुरानी बस्ती में दब्त ठगी के मामलों के खुलासे के लिए पुलिस टीमें गतिविधि कर रही थीं। जांच के दौरान कुववार को अगनी बाजार के पास से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनकी पहचान मोहनमूढ़ नगर निवासी शंकर सोलंकी, मीरा सोलंकी और धावु देवी के रूप में हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तारी और बरामदगी के आार पर मुकदमे में अतिरिक्त धाराएं बढ़ाई गई हैं।

जौहर बस्ती के निधन से शोक की लहर



—भारतीय बस्ती संवाददाता— बस्ती। सुबुसि आलिस-ए-दीन, बेमिनाल मातीबा और शरणा-ए-इस्लाम सोनीना अब्दुल करीम मुजाहिरी जौहर बस्ती, निवासी बनके गांव का 85 वर्ष की आयु में 25 अगस्त को निधन हो गया। वे अपने मासिक-ए-इस्कीरी से जा मिले। लगभग एक सप्ताह से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन से पूरे शैथिल्य जगत में शोक की लहर है।

मरहम अखत सादा मिजाज, मिथावन, अपने मामलों के पक्के, आमतदार और इमानदार व्यक्ति थे। मौलाना मजाहिरेल उलूम सहावरपुर से शिक्षा पूरी करने के बाद, उन्होंने अपने पैतृक गांव बनके में थिखत मदरसा इस्लामिया बैतुल उलूम में अध्यापन कार्य शुरू किया। उस समय मदरसा अपने बुरखाती दौर में था और वे मदरसे के पहले शिक्षक थे। उनके शशिर्ग-ए-रशीद मौलाना अब्दुल समी मुजाहिरी (शिक्षक, बैतुल उलूम, बनके गांव) ने बताया कि वे हमारे उस्ताद थे और हम उनके पहले शशिर्ग में से हैं। उन्होंने अपने कहा कि वे बहुत लगन और मेहनत से पढ़ाते थे। वे एक ओजस्वी वक्ता थे, जिसका प्रभाव पूरे क्षेत्र की जनता पर था। इसी बुखियों के कारण मदरसा जल्द ही तरकीकी की राह पर चल पड़ा।

उन्होंने 1966 से 1995 तक अध्यापन की सेवाएं दीं। इस दौरान उन्होंने 'जवाहिरात' नाम से नितिया कलाम (नात) की एक किताब भी प्रकाशित की। इसे देखकर मशहूर आलिस-ए-दीन और शरानी-ए-इस्लामाब व 'गैर-मनकद' के लेखक मौलाना सादिक बस्ती की कहा था 'ये कहना मुश्किल बात सुन के मसूर से, कि या लाल गुड़जी में गोया घुसा'।

इसके बाद वे बांसी चले गए, जहाँ उन्होंने कोतावली रोड थिखत जामा मसिद के एक महत्वपूर्ण को 'दारुल उलूम रहमिया, बांसी' का रूप दिया। उनकी देखरेख में मदरसा खूब फल-फूल और सफलता हासिल कर चुका है। उनके शशिर्ग के एक लंबी वृक्ष हैं, जो उनके जनजात में लिये जाते हैं। मरहम जनजात और खाल टोनों के बीच सामान्य रूप से लोकप्रिय थे।

होटल में आग से विदेशी नागरिकों समेत 21 की मौत

नई दिल्ली (आम)। दिल्ली के मालविया नगर के पलशरी हट होटल में बुधवार को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 11 विदेशी नागरिक और 10 भारतीय थे। मारे गए विदेशियों में अफ्रीकी देशों और दक्षिणमिस्तान के नागरिक शामिल हैं। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक, मालविया नगर में मौजूद इस होटल के रेस्टोरेंट में सुबह 8.50 बजे आग



लीगी। आग ऊपरी मजिलों पर बने

कमरे और बेसमेंट तक पहुंच गई। फायर टीम ने यहां से 37 लोगों को बाहर निकाला। थिडिंग की फायर एनाओसी नहीं थी। होटल में 25 कमरे हैं। 40 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। कई लोगों की हालत गंभीर है।

आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। थिडले 6 महीनों में दिल्ली में आग की अलग-अलग घटनाओं में 68 लोगों की मौत हो चुकी है।

ममता की टीएमसी टूटी, 58 विधायकों ने अलग गुट बनाया

कोलकाता (आम)। ममता बनर्जी की कंग्रुल कांग्रेस का 28 साल के इतिहास में पहली बार औपचारिक रूप से टूटने पर विधानसभा में 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए विधायक ब्रजव्रत बनर्जी को अपना नेता चुना। विधानसभा स्पीकर रथींद्र बोस को समर्थन प्रदा सा। इसमें भाग की गई कि ब्रजव्रत को नेता विषय घोषित किया जाए।



नृपुण एजेसी के मुताबिक, स्पीकर ने मंजूरी दे दी है। उन्हें विधानसभा में नेता विषय का रूम भी अलॉट कर दिया गया है।

डीएम ने किया तटबंधों का निरीक्षण



—भारतीय बस्ती संवाददाता— बस्ती। जनपद में बाढ़/कटान से सुरक्षा हेतु चलिंत परियोजनाओं एवं बाढ़ पूर्व तैयारी हेतु हरिया तहसील के अनागत घाघरा नदी के बाएं तट पर निर्मित गौरी-लंकावाड, चौदपुर-गौरी, उमरिया रिंग बांध, कटपुरा-चौदपुर तटबंध का निरीक्षण बुधवार को जिलाधिकारी श्रीमती

कुलिका ज्योत्सना द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभिन्ता, बाढ़ कार्य संचालक, द्वारा अनागत करवाया गया कि उमरिया रिंग बांध एवं उसकी परिधि में बसे 12 अदद ग्रामों की सुरक्षा हेतु 02 अदद स्पर का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसकी प्रगति लगभग 50 प्रतिशत है।

महुआ डाबर' महोत्सव 8 से: राष्ट्र भक्तों के पसीने से तर होगी क्रांति की सरजमीं

—भारतीय बस्ती संवाददाता— बहादुरपुर (बस्ती)। महुआ डाबर संग्रहालय द्वारा 8 जून से 10 जून 2026 तक 'महुआ डाबर महोत्सव-2026' का आयोजन बहादुरपुर थिखत साइड थिखत ऐतिहासिक क्रांति थिखत महुआ डाबर में किया जाएगा। शौर्य, शहादत और विरासत की शीम पर आधारित यह तीन दिवसीय महोत्सव भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को समर्पित होगा।



उदरय शहीदों के त्याग और बलिदान की गथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने, युवाओं को अपने इतिहास से जोड़ना तथा स्थानीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण के लिए जागरूक करना है।

महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष 10 जून 1857 को महुआ डाबर में क्रांतिवीर जकर अली एवं उनके साथियों द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध किए गए वीरपूर्ण संघर्ष की स्मृति में किया जाता है। ऐतिहासिक अभिलेखा के अनुसार क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सत्ता को सृनीती देते हुए कई ब्रिटिश अधिकारियों को पारस किया था। इसके प्रतिशोध में ब्रिटिश शासन ने महुआ डाबर गांव को आग के हावक कर दिया और सज्जन अिलेखों में उसे गैर-थिखती घोषित कर दिया। इसी गौरवशाली इतिहास का भी अमरसत यात्रा (हेरिटेज वॉक), गादर सलामी एवं महाल सलामी, महुआ डाबर के इतिहास पर परिचय, स्वतंत्रता संग्राम पर आकाशित भ्रम एवं डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शन, विद्यालयी विद्यार्थियों की देशभक्ति प्रस्तुतियां,

स्वतंत्रता संग्राम साहित्य सम्मेलन, इतिहासकारों, शैथिल्यों एवं लेखकों का संबाद, शहीदों की झांकियां, नाच मन, औपन मादक के माध्यम से कविता, गीत, वक्तव्य एवं लोककला प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे।

महोत्सव में स्वास्थ्य परिक्षण एवं निःशुल्क दवा वितरण शिबिर, युवाओं के लिए कौरियर कारचलिखत सत्र, सांस्कृतिक संस्था, लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, महुआ डाबर संग्रहालय भ्रमण, विरासत संरक्षण संकल्प यात्रा तथा उच्छेद प्रतिभामों एवं सहयोगियों का सम्मान भी किया जाएगा।

महुआ डाबर संग्रहालय के प्रमुख निदेशक एवं क्रांतिकारी वंशज डॉ

कुंआनों नदी बस्ती की जीवन रेखा: इसे स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी-नेहा वर्मा

—भारतीय बस्ती संवाददाता— बस्ती। बुधवार को नदियों को स्वच्छ और अविरोध बनाये रखने की कड़ी में नगर पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा और वरिष्ठ भाजपा नेता अंकुश वर्मा द्वारा कुंआनों नदी के अमरट घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। नेहा वर्मा ने कहा कि कुंआनों नदी की जीवन रेखा है। नदी प्रदूषण का हिकार है। नदियों को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस दिशा में नगर पालिका का चरचरबद्ध प्रयास जारी रहेगा।



भागीदारी से नदियों को स्वच्छ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं। उन्होंने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेते हुये लोगों से आग्रह किया कि जीवन दायिनी नदियों को स्वच्छ रखने की दिशा में अपनी ओर से भी पहल करें। कहा कि सरकार और प्रशासन नदियों को साफ रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, लेकिन

कुंआनों नदी के स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने के बाद अध्यक्ष नेहा वर्मा ने श्रमदान कर रहे कर्मियों का उस्ताहवर्धन किया और निदेश दिए कि सफाई कार्य में किसी भी प्रकार की हिदाला न बरती जाए। उन्होंने कहा कि नदियां हमारी संस्कृति और जीवन का आधार हैं। इन्हें स्वच्छ रखना अमूल्य प्रशासन की नीति, बलिक हर एक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अंकुश वर्मा ने कहा कि नदियों के अस्तित्व को बचाने और उन्हें प्रदूषण मुक्त बनाने के संकल्प में साथ थिखत नदी सफाई अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। कहा कि जन

यह अभियान जनभागीदारी के बिना अधूर है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि नदियों में पौलीथीन, प्लास्टिक या किसी भी प्रकार का कूड़ा-कचरा न फेंके।

सफाई अभियान और निरीक्षण के दौरान पालिका के अध्यक्ष यादव सफाई एवं खाद्य निरीक्षण अधिशासी यादव, विक्रम चौहान, विवेक शीवास्तव, सूर्य गुप्ता, अरुण पाण्डेय के साथ ही नगर पालिका के सभी सफाई न्यायक, बडी संख्या में सफाई कर्मचारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर दूध स्वच्छता अभियान में अपना पूर्ण सहभाग्य देने और आम जनता को जागरूक करने का समूहिक संकल्प लिया।

10 हजार रुपये घूस लेते पकड़ा गया कानूनगो

—भारतीय बस्ती संवाददाता— बस्ती। एंटी कर्षण टीम ने एक कानूनगो को कुववार को 10 हजार रुपए रिश्त लेते रंगे हाथ पकड़ा। वह सदा तहसील में तैनात है। एंटी कर्षण टीम को कानूनगो अशरकी लाल के थिखत रिश्त मांगने की थिखतपत मिली थी। इसके बाद टीम ने मामले की सखवाई पता की। आरोपों की पुष्टि होने पर अफसरों ने



योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कारवाई की। मामला आदरस कोतावली क्षेत्र

सेवा, समर्पण के रूप में मनाया जायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म दिन- अखिलेश सिंह

—भारतीय बस्ती संवाददाता— बस्ती। विश्व हिन्दू महासंघ द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म दिन सेवा और समर्पण के रूप में मनाया जायेगा। जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस अवसर पर तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हरिया तहसील क्षेत्र में थिखत तपसीनाथ में किया गया है। 5 जून को विशाल रक्तदान शिबिर एवं बाबा मोलेनाथ का दिव्य स्मरणिके होगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डीआरजी संजीव त्यागी को मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक डा यशवीर सिंह आमंत्रित किया गया है। बताया कि 6 जून को अथर्वधारागंगा का पाठ शुरु होगा और 7 जून को विशाल हिन्दू सम्मेलन और सहभोज आयोजित किया गया है। इसके मुख्य अतिथि प्रकाश सिंह प्रमुख सचिव और विशिष्ट अतिथि के रूप में डा. मंगलेश कुमार श्रीवास्तव महापौर गोरखपुर, राजमाता राजमहल बस्ती आश्रमा सिंह हिस्सा लेंगी।



-तीन दिवसीय कार्यक्रम में रक्तदान शिबिर, हिन्दू सम्मेलन, सहभोज का आयोजन

गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट कर लौटे विश्व हिन्दू महासंघ जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि उन्होंने तीन दिवसीय कार्यक्रमों के रूप की विस्तार से जानकारी दिया। कहा कि रक्तदान के द्वारा हम दूररे की जान बचाने का माध्यम बनते हैं। प्रयास है कि लगभग 500 यूनिट रक्तदान कराया जाय। बताया कि तीन दिवसीय कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिये पब्लिकरियों में दायित्वों का वितरण कर दिया गया है और तपसी धाम में

महत्त्व जय बसु दास के मार्गदर्शन में जारों से तैयारियां चल रही हैं। अखिलेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के विकास के साथ ही हिन्दू अस्मिता को नयी पहचान दिया है। उनके जन्म दिन को सेवा और समर्पण के रूप में पूरी थिखता और संकल्पों के साथ मनाया जायेगा।

भाजपा कार्यालय पर हुई जन सुनवाई: प्राथमिकता से कराया जायेगा समस्याओं का समाधान- अभिषेक कुमार

—भारतीय बस्ती संवाददाता— बस्ती। जन समस्याओं के प्रभावी निस्तारण हेतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम का चरचरबद्ध आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को जिला महामंत्री अभिषेक कुमार, जिला उपाध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह ने पार्टी कार्यालय पर आये मामलों या फोन पर आये समस्याओं को सुना और सम्बन्धित अधिकारियों को उसके निस्तारण हेतु पहल किया।



जिला महामंत्री अभिषेक कुमार, जिला मंत्री नीलम गौड़ ने जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद कहा कि वे सांवाद अमर प्रकाश हिरीश दिवेदी, पार्टी जिलाध्यक्ष विद्याकान्त मिश्र के दिशा निदेश के अरुणुप जनहित के समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रतिबद्ध हैं। सदैव प्रयास रहता

जिला महामंत्री अभिषेक कुमार, जिला मंत्री नीलम गौड़ ने जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद कहा कि वे सांवाद अमर प्रकाश हिरीश दिवेदी, पार्टी जिलाध्यक्ष विद्याकान्त मिश्र के दिशा निदेश के अरुणुप जनहित के समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रतिबद्ध हैं। सदैव प्रयास रहता

के लिये हर स्तर पर पहल करेंगे। कहा कि इस जन सुनवाई से लोगों की सामान्य समस्या बिलुटी, पानी, सड़क आदि के मामले प्राथमिकता से सुलझ जायेंगे। बताया कि जन सुनवाई में जो मामले आये थे उसके निस्तारण की पहल कर दिया गया है।

शिक्षक संघ की बैठक में गूँजा टेट, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा: संघर्ष पर जोर

—भारतीय बस्ती संवाददाता— बस्ती। बुधवार को प्रेस सलव समागार में उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ की बैठक थिखत जिलाध्यक्ष अंकुश सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में वर्ष 2006 में अनुदात्त विद्यालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक, शिक्षणालय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल किये जाने, टेट की अनिवायता समाप्त कराये जाने के साथ ही स्थानीय शिक्षक समस्याओं के निराकरण कराये जाने पर विचार किया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षक लखवत सिंह, उदरधाम सिंह, धर्मराज यादव, देवमणि वर्मा, चिन्तामणि उपाध्याय, शिवनवल चौधरी, गंगाराम वर्मा, सीताराम को अंग वक्त्र बैठक सम्मानित किया गया।



सम्मानित किये गये सेवा निवृत्त शिक्षक

मुख्य अतिथि के रूप में बैठक को संबोधित करते हुये संघ के प्रदेश संयोजक मंत्री वरिष्ठ दत्त पाण्डेय ने कहा कि अनुदात्त विद्यालयों के शिक्षक घोर उपेक्षा के थिकार हैं और उन्हें अपना अधिकार तक नहीं मिल पा रहा है। संघ की

बैठक में वीरेंद्र कुमार मिश्र, लखवत सिंह, उदरधाम सिंह, धर्मराज यादव, राजेन्द्र प्रसाद दूबे, धर्मराज चौधरी, चिन्तामणि आदि ने सम्वोधित करते हुये थिखतवार शिक्षक समस्याओं को रखा और जोर दिया कि अधिकार के लिये संघर्ष तैयार करते हुये सरकार पर नीतिगत दबाव बनाया जाय। अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष अंकुश सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ की बैठक में मुख्य रूप से राम मूर्ति यादव, देवेन्द्र कुमार शुक्ल, नानासिंह, रामतीर्थ यादव, भानु प्रताप शुक्ल, रामरंजण, राममूर्ति वर्मा, परशुराम सिाद, विजय बहादुर सिंह, वृंशेश कुमार सिंह, डॉ. राजेन्द्र सिंह आदि उपस्थित रहे।

"युद्ध अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेदेल फिलिप्स

भारतीय बस्ती

बस्ती 4 जून 2026 गुरुवार

सम्पादकीय

स्कूलों में त्रिभाषा की शिक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीएसई, और एनसीईआरटी को नोटिस जारी करके यह निर्देश दिया है कि वे 1 जुलाई 2026 से सभी सीबीएसई स्कूलों में नवीं के विद्यार्थियों के लिए तीन-भाषा फार्मुला लागू करने के अपने इंतजामात के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करें। बीते 27 मई को, सीबीएसई के इस कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनते हुए, शीफ अदालत ने तुरंत कोई स्थगनादेश देने से मना कर दिया, लेकिन यह माना कि "कठिनाई और असुविधा" को लेकर चिंताओं की समीक्षा की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट 15 और 16 जुलाई को दलीलें सुनेगा। जिस अगंभीर टंग से सरकार अपनी विवादप्रस्त भाषा नीति लागू करने के लिए सीबीएसई का इस्तेमाल कर रही है, वह एक बार फिर विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को प्रतीवृत्त उपेक्षा-भाव को दिखाता है। इसी 15 मई को, सीबीएसई ने एक परिपत्र जारी कर 1 जुलाई से नवीं के विद्यार्थियों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया। इसके लिए नयी शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और 'स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रमां रूपरेखा 2023' के साथ संगति का हवाला दिया गया। तीन से कम—कम दो ही देशी भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। फ्रेंच या जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं तीसरी भाषा के रूप में केवल तभी ली जा सकेंगी जब पहली दो भाषाएं भारतीय हों, या फिर वैकल्पिक चौथे विषय के रूप में ली जा सकेंगी। विद्यार्थियों के सामने खड़ी की गयी कठिनाई पर पर्दा डालने की तुच्छ कोशिश में, सीबीएसई ने दसवीं के बोर्ड इतिहास से तीसरी भाषा को छूट दे दी, जिसका मूल्यांकन स्कूल-आधारित आंतरिक मूल्यांकनों के जरिए किया जायेगा। हालांकि, इसके अंक अंतिम प्रमाणपत्र में अब भी मौजूद रहेंगे।

बहुमूल्य कुछ हफ्ते पहले, सीबीएसई ने कहा था कि तीसरी भाषा की जरूरत को अकादमिक वर्ष 2029-30 तक टाला जायेगा। लेकिन अचानक विषय बदलने की केवल एक वजह हो सकती है कि यह राजनीतिक निर्णय है। इस कदम को कई आधारों पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है, जिसमें संवैधानिक आधार भी शामिल है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि भाषा व्यक्तिगत संघर्ष का मामला है और इसे राज्य सत्ता द्वारा थोपा नहीं जा सकता। यह भी कहा जा रहा है कि जिस एनईपी 2020 के नाम पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है, वह लचीलेपन का वादा करती है और यह गारंटी देती है कि किसी विद्यार्थी या किसी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जायेगी। याचिकाकर्ताओं की यह भी दलील है कि बतौर कार्यकारी निकाय सीबीएसई के पास संसद से बने कानून के समर्थन के बगैर इतना व्यापक शैक्षिक आदेश लागू करने का अधिकार नहीं है, भले ही एनईपी में कुछ भी कहा गया हो, क्योंकि उसमें जो कहा गया है वह एक कार्यपालकीय नीति की मंशा है, न कि कानून। माता-पिता और शिक्षक बोर्ड इतिहास से ठीक पहले विद्यार्थियों पर इस अतिरिक्त दबाव को लेकर चिंतित हैं।

तमिलनाडु लगातार त्रि-भाषा फॉर्मूला के विरोध करता आया है। 1937 में सी राजगोपालाचारी की अध्यक्षता वाली तत्कालीन मद्रास सरकार ने वहां के स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई अनिवार्य कर दी थी। जस्टिस पाटी और परियार जैसे द्रविड़ नेताओं ने बड़े पैमाने पर इस फैसले का विरोध किया था। 1940 में इस नीति को रद्द कर दिया गया, लेकिन हिंदी विरोधी भावनाएं बरकरार रहीं।

साल 1968 में जब त्रि-भाषा फॉर्मूला पेश किया गया था, तब तमिलनाडु ने इसे हिंदी को थोपने का प्रयास करार देते हुए इसका विरोध किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई के नेतृत्व में तमिलनाडु ने दो-भाषा नीति अपनाई थी, जिसके तहत केवल तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी।

स्कूल प्रशासकों ने प्रैशिक्षित भाषा-शिक्षकों की कमी और उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों की अनुपलब्धता की ओर ध्यान रखा है। स्कूली शिक्षा को सांस्कृतिक युद्धभूमि में बदलने से उन्मत्त मानव संसाधन का वैश्विक भंडार बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को कोई मदद नहीं मिलने वाली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले पर दोबारा सुनवाई किए जाने से पहले केंद्र को अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए।

उमुगांडा से मनोरमा तक: सामूहिक संकल्प की यात्रा



—अखिल कुमार यादव—

किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसकी आर्थिक संपन्नता, विशाल इमारतों या आधुनिक तकनीक में नहीं, बल्कि उसके नागरिकों की सामूहिक चेतना और सामाजिक जीवन के प्रति उनकी जिम्मेदारी में निहित होती है। जब लोग यह समझने लगते हैं कि स्वच्छ सड़कें, सुरक्षित पर्यावरण, स्वच्छ नदियां और संरक्षित प्राकृतिक संसाधन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा धरोहर हैं, तब विकास का एक नया अध्याय शुरू होता है।

युनिया के अनेक देशों ने जन्मागीदारी की इसी शक्ति के बल पर उल्लेखनीय परिवर्तन किए हैं। अफ्रीकी देश रवांडा की पशुमाला परंपरा और उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में मनोरमा (मनवर) नदी के संरक्षण के लिए चलाया गया अभियान इसी विचारधारा के दो प्रेरक उदाहरण हैं। रवांडा में 'उमुगांडा' केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को नागरिक अपने निजी कार्यों को कुछ समय के लिए निरम देकर सार्वजनिक हित के कार्यों में भाग लेते हैं। लोग सड़कों की सफाई करते हैं, सार्वजनिक स्थलों का रखरखाव करते हैं, वृक्षांशण करते हैं, जल स्रोतों को संरक्षित करते हैं और अपने आपसावक के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए श्रमदान करते हैं। इस परंपरा ने रवांडा को दुनिया के सबसे स्वच्छ देशों में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे यह सिद्ध होता है कि जब नागरिक स्वयं परिवर्तन के वाहक बन जाते हैं, तब



सीमंत संसाधनों के बावजूद असाधारण उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं।

भारत में भी सामुदायिक श्रम और जन्मागीदारी की परंपरा नहीं नहीं है। गांवों में तालाबों की सफाई, कुओं का निर्माण, मार्गों की मरम्मत और धार्मिक-सामाजिक आयोजनों में सामूहिक श्रमदान की परंपरा सदियों से चली आ रही है। महान्या गांधी से स्वच्छता और श्रमदान को राष्ट्र निर्माण का आधार माना था। उनका मानना था कि समाज का उत्थान तभी संभव है जब लोग स्वयं अपने परिवेश की जिम्मेदारी स्वीकार करें। विनोबा जी और जवाहरलाल नेहरू जैसे समाज सुधारकों ने भी सामुदायिक सहयोग को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम बताया था। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण और जल संकट जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, तब जन्मागीदारी का महत्व और बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र संहिता अनेक वैश्विक संस्थाएं वेतानवी दे चुकी हैं कि आने वाले दशकों में जल संकट मानव सभ्यता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा। बढ़ती आबादी, अनियंत्रित शहरीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने नदियों और जल स्रोतों पर भारी दबाव डाला है। ऐसे समय में नदियां का संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं, बल्कि मनुष्य की पीढ़ियों के अस्तित्व का प्रश्न बन गया है। भारत की

सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई है। गंगा, यमुना, सरयू, गोमती, नर्मदा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां केवल जलधाराएं नहीं हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और जीवन की आधारशिला हैं। इन्होंने अनेक तटों पर नगर बसे, कृषि का विस्तार हुआ और सभ्यताओं ने जन्म लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश आधुनिक विकास की दौड़ में अनेक नदियां प्रदूषण और अतिक्रमण का शिकार हो गईं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद से होकर बहने वाली पौराणिक मनोरमा नदी भी लंबे समय तक इसी संकट से जूझती रही। मनोरमा नदी केवल एक जलधारा नहीं है, बल्कि बस्ती और आसपास के क्षेत्रों की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्थानीय जनसुविधियों और सामूहिक मान्यताओं में इसका विशेष स्थान माना जाता है। समय के साथ बहते प्रदूषण, प्लास्टिक कचरे और उष्ण के कारण नदी का स्वरूप प्रभावित होने लगा। कई स्थानों पर इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि नदी नाले जैसी दिखाई देने लगी। नदी के किनारे संकट के डेर जमान होने लगे और जल प्रवाह भी प्रभावित होने लगा। यह स्थिति केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि स्थानीय समाज की सांस्कृतिक विरासत के लिए भी चिंता का विषय बन गई।

इसी दौरान बस्ती के युवा पर्यावरण प्रेमी आकाश गुप्ता और उनके साथियों ने एक ऐसा कदम

उठाया, जिसने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने मनोरमा नदी की सफाई और संरक्षण का संकल्प लिया। शुरूआत में यह प्रयास कुछ लोगों का छोटा-सा अभियान था, लेकिन धीरे-धीरे यह जन्मागीदारी का उदाहरण बन गया। बताया जाता है कि लगातार कई सप्ताह तक श्रमदान करते हुए टीम ने नदी से हजारों किलोग्राम प्लास्टिक और अन्य कचरा निकाला। उन्होंने इस पहल को जनजाति, श्रमदान और पर्यावरणीय चेतना का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए कहा कि ऐसे प्रयास पूरे देश के लिए प्रेरणा हैं। प्र. आर.सी. की यह सहारना न केवल बस्ती जनपद के लिए गौरव का विषय है, बल्कि यह भी प्रमाणित करती है कि स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ एक छोटा प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन की प्रेरणा बन सकता है।

इस अभियान ने यह भी सिद्ध किया कि युवा केवल मनुष्य नहीं, बल्कि वर्तमान के भी परिवर्तनशील नेतृत्वकर्ता हैं। जब युवा किसी उद्देश्य को अपना मिशन बना लेते हैं, तो समाज में गहरा संस्कार बदलाव की नई संभावनाएं जन्म लेते हैं। आकाश गुप्ता और उनके साथियों का प्रयास इस बात का प्रमाण है कि एक छोटा समूह भी बड़े सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत कर सकता है। उनके कार्य ने यह संदेश दिया कि उपर्युक्त संस्कार के लिए बड़े बजट या विशाल संसाधनों से अधिक आवश्यक है।

सकरी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है। यदि नागरिक स्वयं आगे आए, तो वे अपने क्षेत्र की तस्वीर बदल सकते हैं। यही वह मानना है जो सड़कों की उमुगांडा परंपरा में दिखाई देती है और यही भावना भारत के विभिन्न सामाजिक अभियानों में भी दिखाई पड़ती है।

31 मई 2026 को प्रसारित अपने महक शेरियों कार्यक्रम ध्वन की बात के 134वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्ती जनपद की पौराणिक मनोरमा नदी के संरक्षण और सफाई के लिए कार्य कर रही युवा टीम की विशेष प्रशंसा की। उन्होंने आकाश गुप्ता और उनके साथियों के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ युवाओं ने विना किसी शिकायत के स्वयं जिम्मेदारी उठाई और नदी को स्वच्छ बनाने का अभियान शुरू किया। प्रमाणित नों बताया कि यह टीम जल, फावड़े और टोकरीयों के साथ नदी में उतरकर प्रतिदिन बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों निकालती रही, जिसके परिणामस्वरूप नदी के एक हिस्से में फिर से स्वच्छ जल प्रवाह दिखाई देने लगा। उन्होंने इस पहल को जनजाति, श्रमदान और पर्यावरणीय चेतना का उत्कृष्ट उदाहरण बताते हुए कहा कि ऐसे प्रयास पूरे देश के लिए प्रेरणा हैं। प्र. आर.सी. की यह सहारना न केवल बस्ती जनपद के लिए गौरव का विषय है, बल्कि यह भी प्रमाणित करती है कि स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ एक छोटा प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन की प्रेरणा बन सकता है।

इस अभियान ने यह भी सिद्ध किया कि युवा केवल मनुष्य नहीं, बल्कि वर्तमान के भी परिवर्तनशील नेतृत्वकर्ता हैं। जब युवा किसी उद्देश्य को अपना मिशन बना लेते हैं, तो समाज में गहरा संस्कार बदलाव की नई संभावनाएं जन्म लेते हैं। आकाश गुप्ता और उनके साथियों का प्रयास इस बात का प्रमाण है कि एक छोटा समूह भी बड़े सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत कर सकता है। उनके कार्य ने यह संदेश दिया कि उपर्युक्त संस्कार के लिए बड़े बजट या विशाल संसाधनों से अधिक आवश्यक है।

भारतीय पत्रकारिता की गिरती शारख



—निर्मल रानी—

पेरिस—आधारित अंतरराष्ट्रीय संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वार्षिक रूप से जारी किये जाने वाले विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार यह भारतीय पत्रकारिता की रैंकिंग पर नजर डालते तो 2026 में यह 180 देशों में 157 वें स्थान पर है। पिछले वर्ष से यह रैंकिंग 62 अंक नीचे गिरी है। यह स्थिति विश्व में भारतीय पत्रकारिता की बहुत गंभीर श्रेणी की तरह इशारा करती है। जबकि नॉर्वे, एस्तोनिया व नीदरलैंड्स जैसे देशों के नाम इस सूची में शीर्ष पर हैं। चिंता की बात तो यह है कि पड़ोसी देश नेपाल,मालदीव व श्रीलंका जैसे देशों की स्थिति भी भारत से बेहतर है। गंगा भारत में प्रेस स्वतंत्रता इस समय संकट के दौर से गुजर रही है जिसकी वजह सत्ता का नियंत्रण,राजनीतिक दबाव, अव्यक्त डिजिटल निगरानी,विज्ञापन की तालब,मीडिया घरानों पर सत्ता से जुड़े लोगों का नियंत्रण व अत्याचार के साथ होने वाली हिंसा व अत्याचार प्रमुख कारण हैं। यही वजह है कि भारतीय मीडिया शगोटी मीडिया 'के नाम से भी प्रचलित हो रहा है। हालांकि सत्ता की याचिकाओं के इसी दौर में युद्ध भी मीडिया 'से जुड़े रहे अनेक इमानदार पत्रकार अपने निजी यू ट्यूब चैनल चलाकर भारतीय मीडिया की साख बचाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं।



पर आम जनता की लगनले सुनने के बाद भी यह 'गोपी चक्रवर्ती' इमानदारी से पत्रकारिता का दायित्व निभाने के बजाय अपने बेतुके बोल,सत्ता के प्रति अनिष्ठा 'पत्रकारिता' व अज्ञानता पूर्ण बातों के चलते आम लोगों की नफरत का पोषण बन रहा है। यही वजह है कि 'शो पेशि' स्प्री इन एंकरों व इनके टी वी चैनलस की लोकप्रियता व अनेक देशों की संस्था जहां दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है वहीं यू ट्यूब चैनल व सोशल मीडिया जैसे जुड़े इमानदार पत्रकारों के दरिद्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों मीडिया 'से जुड़े एक प्रसिद्ध टी वी चैनल के एक प्रसिद्ध महिला एंकर अज्ञान और कथपन में एक लाइव शो के दौरान हुए एक अमर टिप्पणी करते हुए 'यू ट्यूब टीचर्स' और 'ऑनलाइन एजुकेटर्स' पर निशाना साधा। उन्होंने 'यू ट्यूब टीचर्स' के अलावे जो 'कोई नहीं' परीक्षा, टिप्पण यूट्यूबर और 'भाई के बीटिंग' जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। अपनी बबलास में उन्होंने कहा कि यूट्यूब स्टार टीचर्स को 'दो कोड़ी का ज्ञान भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि मीडियेशन के नाम पर ये शिक्षक केवल व्यवस्था के नाम के लिए कट्टे बनाते हैं। कम जांचकारी के कारण ऐसे टीचर्स छात्रों को गुमराह कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये शिक्षक भ्रामक हेडलाइन्स लिखकर व्यूज बढ़ाते हैं।

इस गंभीर रिपोर्ट्स परा व अपमानजनक टिप्पणी के बाद शरक के अनेकनेक प्रतिष्ठ यू ट्यूबरस विश्व शिक्षकों,ऑनलाइन एजुकेटर्स व उनके छात्रों व समर्थकों का गुस्सा इस

दल गया। इस अपील पर तमाम नये लोगों ने जिम की सदस्यता भी लेकर दीपक की आर्थिक मदद की। परन्तु अमन चोपड़ा नामक इसी गोपी मीडिया के एक बंदनम युवा एंकर ने इस खबर को नकारात्मक रूप में पेश करते हुये अपनी ओधी व घटिया टिप्पणी में दीपक की आर्थिक तलाश का मजाक उड़ाते हुए और उसपर तंज कसते हुये कहा कि 'सेंसेयुलरिजम का बजट नहीं उठा पाए' पहलवान दीपक, ओ सॉरी, मोहम्मद दीपक। उसने यह भी कहा कि 'नाम के आगे 'मोहम्मद' लगाने से भी उनके विचार को पालंग कर दिया गया।' मोहम्मद दीपक के लिए, कोई मोहम्मद उस तरह से खड़ा नहीं हुआ। इस नफरती एंकर ने आर्थिक संकट के समय दीपक का कोजदार उडया जसमिक दीपक ने काजदार घटना के समय धर्म नहीं बल्कि केवल इतिहास की धरती पर आया है। दखलाल यह उन्ही कथित 'बनकरों' का निरोध है जिनसे 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के समय एक एक गोपी बनेल पाकिस्तान के 5 शहर तहाह होना का दावा कर रहा था तो दूसरे बनेल ने कहा था कि 25 शहर तहाह हो गए। यह वहीं एंकर हैं जो 'रुडियोजी' में बंदरों की तरह उछलते हैं और अमर शब्दावली का प्रयोग यहाँ तक कि लड़कें व मारपीट को भी प्रोत्साहित करते रहते हैं। यह कथित पत्रकार 6 र्म—जाति के आहार पर समाज बांटने वाली बात करते हैं तथा 2000 की भी बंदनम करते हैं। ऐसे अनेक लोग कभी किसी अपराध में जेल जा चुके हैं तो कभी अपने भ्रामक बयानों के लिये न्याय मजम चुके हैं। अपना भ्रामक व गुमराह करने वाले डिजिटल हिंसे करने में भी इन्हें नफरत हासिल है। अदालती घटककार भी इन्हें अज्ञात दिन सुनने को तिलती रहती है। सत्ता की सुझामरु कर समाज में नफरत फैलाकर केवल बनेल बनेल बनेल ऐसे लोगों को पत्रकार नहीं बल्कि 'पथकर' कहना जयदा नुमासिह होगा।

वैटिलेटर पर देश की परीक्षा समीक्षा

—योगेश कुमार गोयल—



भारत में परीक्षा अब केवल योग्यता का आकलन नहीं रह गई है बल्कि यह करोड़ों सपनों की निर्णयक कसौटी बन चुकी है लेकिन जब यही कसौटी बार-बार सफाई हो जाए, जल महान्त और ईमानदारी की जगह 'जुगाड़' और 'माफिया नेटवर्क' हावी हो जाएं, तब यह केवल परीक्षा का संकट नहीं बल्कि राष्ट्र के मनुष्य का संकट बन जाता है। पेपर लीक के चलते नीट-यूजी 2026 परीक्षा रह होना, सीबीएसई की ऑन स्कैन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली पर उठे गंभीर सवाल और एसएससी जेडी परीक्षा में शकाली, वी चेतना मिलकर यह सुधार क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट के डिप्टिगणों, जांच समितियों और सिफारिशों के बावजूद 2026 में स्थिति और बदतर कैसे हो गई? इसका सीधा अर्थ है कि समस्या तकनीकी कम और इच्छाशक्ति की अधिक है।



राष्ट्र की परीक्षा प्रणाली का बांध ही कई स्तरों पर कमजोर है। प्रश्नपत्रों की छपाई से लेकर वितरण तक की प्रक्रिया में निजी एजेंसियों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बड़ी भूमिका रहती है। यही सब जगह है, जहां से माफिया नेटवर्क अपनी जड़ें जमाता है। इस प्रणवत्र प्रणाली कंडं तक पहुंचने से पहले ही स्कैन होकर डिजिटल रूप में चलने लगते है तो यह स्पष्ट संकेत है कि सुरक्षा तंत्र केवल कागज़ पर मजबूत है, उभरी पर नहीं। दूसरी ओर, कोयिंग जमान का अनियंत्रित विस्तार इस संकट को और गहरा कर रहा है। तदिक और इंजीनियरिंग प्रश्नों पर सफाई एवं हजारों करोड़ रुपये का ब्याज व और 'इंसानवादी एरर्स' जैसे बूटे वुद्धे का प्रयोग है। इस बाजार में 'सफरता' एक उपाय है, लिये खरीदने के लिए छात्र और अभिभावक किसी भी हद तक जाने को मजबूर हैं। इसी मानसिकता का फायदा उठाकर एजुकेशन माफिया सौतेल कर, 100 प्रतिशत संलेखन गारंटी और 'इंसानवादी एरर्स' जैसे बूटे वुद्धे का प्रयोग है। यदि नीट प्रकरण परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है तो सीबीएसई का ओएसएम विवाद मूल्यांकन प्रणाली की विवरसनीयता पर गंभीर चोट करता है।

